भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 112 का उत्तर

गति शक्ति प्लेटफॉर्म

112. श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गति शक्ति प्लेटफार्म से कई रुकी हुई रेल परियोजनाओं में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान, राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र और ओडिशा में गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कितनी रेल परियोजनाओं में तेजी आई है;

(ग) गति शक्ति के अंतर्गत रेल परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है और ऐसी विभिन्न परियोजनाओं पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल का उपयोग किस हद तक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं के समय और लागत में कटौती करने में रेलवे की सहायता कर रहा है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा की पटल पर रख दिया गया है।

****

गति शक्ति प्लेटफॉर्म के संबंध में दिनांक 07.12.2022 को लोक सभा में श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री चंद्र शेखर साहू, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्री गिरीश भालचन्द्र बापट के अतारांकित प्रश्न सं. 112 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) : जी हां।

(ख) और (ग): रेल परियोजनाएं जोनल रेलवे वार स्वीकृत/निष्पादित की जाती हैं न कि राज्यवार क्योंकि रेलवे की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के बाहर फैली हो सकती हैं।

गति शक्ति प्लेटफॉर्म के तहत, पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे में लगभग 14,199 करोड़ रुपये की लागत से 1043 किमी की कुल लंबाई की 36 परियोजनाओं (5 नई लाइन, 9 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली 84 किलोमीटर की कुल लंबाई की 1 आमान परिवर्तन परियोजना शामिल है, जिसकी लागत 955 करोड़ रुपये है और ओडिशा राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली 625.82 करोड़ रु. की लागत वाली 32.16 किलोमीटर की कुल लंबाई की 3 परियोजनाएं (2 नई लाइन और 1 दोहरीकरण) शामिल हैं। ।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेलवे परियोजनाओं का जोनल रेलवे-वार विवरण भारतीय रेलवे की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways > Railway Board > About Indian Railways > Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Rail Budget/Pink Book (Year)> Railway wise Works Machinery and Roiling Stock Programme पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं : (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड

स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी के लिए और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुसरण करना। इससे 2014 से चालू करने की दर में काफी वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र:

01.04.2022 तक, 280,079 करोड़ रुपये की लागत वाली 6,118 किलोमीटर लम्बाई की 34 रेलवे परियोजनाएं (16 नई लाइनें, 2 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण), पूरी तरह से/आंशिक रूप से महाराष्ट्र में आती हैं, जो योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1154 किलोमीटर लंबाई चालू को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 21,297 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2014 से, रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के रेल बजट आवंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि की गई है। 2014-19 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान, 1,171 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 4,801 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 310% अधिक है। इन आबंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 7,281 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 522% अधिक) और वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 6,700 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 472% अधिक) कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु 8,547 करोड़ रु. का वार्षिक बजट आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक परिव्यय की तुलना में 630% अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु

अभी तक का सर्वाधिक 11,903 करोड़ रु. का बजट आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक परिव्यय (1171 करोड़ रु. प्रति वर्ष) की तुलना में 916% अधिक है।

2014-22 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1,141 कि.मी. खंड (118 कि.मी. नई लाइन, 136 कि.मी. आमान परिवर्तन और 887 कि.मी. दोहरीकरण) को 142.69 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है, जो 2009-14 की औसत वार्षिक कमीशनिंग (58.4 किमी. प्रति वर्ष) से 144% अधिक है।

ओडिशाः

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4,609 किमी की कुल लंबाई वाली 55,759 करोड़ की लागत की 35 परियोजनाएं (11 नई लाइन, 1 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1039 किमी. लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 21,729 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है।

वर्ष 2014-19 के दौरान ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन को 838 करोड़ रु. प्रति वर्ष (2009-14 के दौरान) से बढ़ाकर 4,126 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया है जो 2009-14 के दौरान औसत बजट आवंटन से 392 प्रतिशत अधिक है। इन आवंटनों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 4,568 करोड़ रूप किया गया (2009-14 के औसत वार्षिक आबंटन से 445 प्रतिशत अधिक) और 2020-21 में 5,296 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक आबंटन से 532% अधिक) और 2021-22 में 6,471 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 672% अधिक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, इन परियोजनाओं के लिए

9,734 करोड़ रु. का अब तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय प्रदान किया गया, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन (838 करोड़ रु./वर्ष) से 1062 % अधिक है।

2014-22 के दौरान, ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1,135 कि.मी. खंड (264 कि.मी. नई लाइन और 871 कि.मी. दोहरीकरण) को 141.88 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है, जो 2009-14 की औसत वार्षिक कमीशनिंग (53.4 किमी प्रति वर्ष) से 166% अधिक है।

(घ): योजना और अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं के निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर, 21 में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरूआत की गई थी। एनएमपी का उद्देश्य मल्टी-मॉडल संपर्कता विकसित करने और देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाने के समग्र उद्देश्य के साथ दोहराव से बचने और कीमती राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए रेलवे, नौपरिवहन, सड़क मार्गों, दूरसंचार, पाइपलाइनों आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच सहक्रियता लाना है। मेक इंडिया पहल के साथ घटी हुई लागतें भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बेहतर करेगी। भारतीय रेल ने अपने परियोजना योजना प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को तत्काल समाहित कर लिया है। बीसेग-एन द्वारा विकसित गति शक्ति जीआईएस प्लेटफार्म पर 342 से अधिक रेलवे परियोजनाओं को मैप किया गया है।

****